Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 8

राजस्थान की अर्थव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

विषयसूची

S No.	Chapter Title	Page No.
1	राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य	1
2	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र	5
3	ग्रामीण विकास और पंचायती राज	18
4	औद्योगिक विकास	26
5	आधारभूत संरचना और संसाधन	39
6	सेवा क्षेत्र	45
7	राजस्थान में शहरी विकास	52
8	राजस्थान की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं	61
9	राज्य वित्त एवं विकास के अन्य संसाधन	86
10	अन्य सामाजिक क्षेत्र योजनाकार्यक्रम	91
11	सतत विकास लक्ष्य– राजस्थान में मुद्दे और चुनौतियाँ	102
12	बजट 2024–25	105

पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न

प्रश्न 1 इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए: (2023)

(i) यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती हैं।

(ii) पंजीकरण के बाद, पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोज़गार उपलब्ध करवाया जाता है।

(1) न तो (i) न ही (ii) सही है ।
(2) (i) व (ii) दोनों सही है ।
(3) केवल (ii) सही है।
(4) केवल (i) सही है ।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 2 निम्नांकित में से कौन सा विकल्प (इंदिरा महिला) शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य बताता है ? (2023)

(1) महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना ।
(2) मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबन्धन के बारे में जागरूकता पैदा करना ।
(3) महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ।
(4) बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार ।
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 3 चुकन्दर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था । (2023)

(1) श्री गंगानगर में
(2) भोपालसागर में
(3) केशोरायपाटन में
(4) उदयपुर में
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 4 निम्नांकित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वॉटर सिवरेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है ? (2023)

(1) राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस एंड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(2) राजस्थान आवास विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(3) राजस्थान हाउसिंग बोर्ड
(4) राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 5 निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है - "कोई भूखा न सोए" ? (2023)

(1) 'बालगोपाल योजना
(2) इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना
(3) अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना
(4) इंदिरा रसोई योजना
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 6 वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है ? (2023)

(1) 6.54 प्रतिशत
(2) 5.18 प्रतिशत
(3) 4.86 प्रतिशत
(4) 3.78 प्रतिशत
(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 7 राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है ? (2023)

(1) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

(2) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

(3) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 5 करोड़ तक के ऋणों पर 6 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

(4) इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋणों पर 8 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 8 वर्ष 2022-23 में, राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा ? (2023)

(1) परिवहन, भण्डारण एवं संचार

(2) व्यापार, होटल एवं जलपान गृह

(3) स्थावर सम्पदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएँ

(4) वित्तीय सेवाएँ

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 9 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA (स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर) में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है ? (2023)

(1) इनमें से कोई नहीं (2) सेवा क्षेत्र

(3) उद्योग क्षेत्र (4) कृषि क्षेत्र

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 10 राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम-II परियोजना के अन्तर्गत 801 कि.मी. लम्बाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है ? (2023)

(1) नाबार्ड (2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(3) विश्व बैंक (4) एशियन विकास बैंक

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 11 राजस्थान में किस एजेंसी को पी.एम. - कुसुम योजना (कम्पोनेंट A) के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावॉट से 2 मेगावॉट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किये जाने हैं ? (2023)

(1) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिऐंसी (2) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(3) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (4) राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 12 राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया ? (2023)

(1) 2008 (2) 2005

(3) 2003 (4) 2001

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 13 निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है ? (2023)

(1) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एस.पी.एम.आर.एम.)

(2) महात्मा गांधी जन-भागीदारी विकास योजना (एम.जी.जे.बी.वाय.)

(3) डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम

(4) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाय.)

(5) अनुत्तरित प्रश्न

प्रश्न 14 राजस्थान में अटल भू-जल योजना के लिये निम्न में से कौन सा/से कथन सही है/हैं ? (2023)

(a) अटल भू-जल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है ।

(b) इस योजना का फोकस भू-जल प्रबन्धन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है।

नीचे दिये गये कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिये :

(1) न तो (a) न ही (b) (2) केवल (b)

(3) केवल (a) (4) (a) और (b) दोनों

(5) अनुत्तरित प्रश्न

विश्लेषण- RPSC का रुझान बताता है कि RAS परीक्षा में प्रतिवर्ष राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न सामान्यतः सरल और तथ्यात्मक होते हैं, जिन्हें सही तथ्यों की जानकारी से आसानी से हल किया जा सकता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के व्यापक दृष्टिकोण जैसे स्थिर और चालू कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP), भारतीय अर्थव्यवस्था में GSDP का हिस्सा, तथा स्थिर और चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसके अलावा, कमजोर वर्गों जैसे महिलाएं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और प्रौढ़ जनसंख्या पर आधारित प्रश्न भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस संदर्भ में प्रमुख(flagships) और हाल ही में शुरू की गई योजनाएं अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती हैं, विशेषकर योजनाओं की शुरुआत की तारीख, उद्देश्य और लाभार्थियों से जुड़े तथ्य महत्वपूर्ण है।

आर्थिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे पर आधारित प्रश्न भी अंक बढ़ाने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए, चालू और स्थिर कीमतों पर GSVA (Gross State Value Added) में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, किसी विशेष क्षेत्र में उप-क्षेत्रों का योगदान और उनकी विकास दर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर, पवन और बायोमास से जुड़े प्रश्न भी अक्सर देखने को मिलते हैं। बुनियादी ढांचे और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संदर्भ में, परियोजना की वित्तपोषण एजेंसी का नाम, उद्देश्य और कार्यान्वयन के क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

इसके अलावा, प्रमुख नीतियां और उनके प्रावधान, वित्तीय संसाधन और FRBM अधिनियम, सतत विकास लक्ष्य (SDG) सूचकांक और जिलों की रैंकिंग से जुड़े प्रश्न भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। बजट के संदर्भ में उत्कृष्टता केंद्र, विभिन्न संस्थानों के स्थान, और हाल ही में शुरू की गई योजनाओं के उद्देश्य और आदर्श वाक्य पर प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा की तैयारी में इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है ताकि अधिकतम अंक अर्जित किए जा सकें।

1 CHAPTER राजस्थान की अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य

राजस्थान की रूपरेखा

- राजस्थान जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग कि.मी. है, जो कि 7 संभागों और 41 जिलों में विभक्त है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है जो की सर्वाधिक है।

राज्य के प्रमुख संकेतकों का भारत से तुलनात्मक विवरण				
संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्र	2011	लाख वर्ग किमी.	3.42	32.87
जनसंख्या	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर	2001-2011	प्रतिशत	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	प्रति वर्ग किमी. जनसंख्या	200	382
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या	2011	प्रतिशत	24.9	31.2
अनुसूचित जाति की जनसंख्या	2011	प्रतिशत	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	2011	प्रतिशत	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं	928	943
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	2011	प्रति हजार पुरुष बच्चों पर महिला बच्चे	888	91
साक्षरता दर	2011	प्रतिशत	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरुष)	2011	प्रतिशत	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला)	2011	प्रतिशत	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर	2011	प्रतिशत	43.6	39.8
अशोधित जन्म दर	2020*	प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या	23.5	19.5
अशोधित मृत्यु दर	2020*	प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या	5.6	6.0
शिशु मृत्यु दर	2020*	प्रति हजार जीवित जन्म	32	28
मातृ मृत्यु अनुपात	2018-20*	प्रति लाख जीवित जन्म	113	97
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा	2016-20*	आयु वर्षों में	69.4	70.0

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी निश्चित समयावधि के दौरान राज्य में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का है।

वर्ष 2023-24	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष- 2011-12)	वृद्धि दर	प्रचलित मूल्यों पर	वृद्धि दर
राजस्थान	8.45 लाख करोड़	8.03%	15.28 लाख करोड़	12.56%
भारत	173 लाख करोड़	8.2%	295 लाख करोड़	9.6%

नोट: भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान का योगदान – स्थिर मूल्य पर (4.86%) प्रचलित मूल्य पर (5.17%)

शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

NSDP = GSDP - स्थायी पूंजीगत उपभोग

वर्ष 2023-24	स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष- 2011-12)	वृद्धि दर	प्रचलित मूल्यों पर	वृद्धि दर
राजस्थान	7.41 लाख करोड़	8.10%	13.69 लाख करोड़	12.70%

सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

- GSVA = जीएसडीपी – कर + सब्सिडी
- इसका उपयोग राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान को दर्शाने के लिए किया जाता है

GSVA- प्रचलित मूल्यों पर	भारत	राजस्थान
कृषि क्षेत्र	17.66%	26.22%
औद्योगिक क्षेत्र	27.62%	28.21%
सेवा क्षेत्र	54.72%	45.07%

स्थिर मूल्यों पर	योगदान	वृद्धि
कृषि	26.21%	2.13%
उद्योग	29.84%	12.43%
सेवा	43.95%	6.37%

प्रति व्यक्ति आय

- प्रति व्यक्ति आय की गणना शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है।
- प्रति व्यक्ति आय = NSDP/राज्य की मध्यवर्षीय कुल जनसंख्या
- प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय-
  - ✓ वर्ष 2023-24 - ₹1,67,964 (अनुमानित)
  - ✓ वर्ष 2022-23 - ₹1,50,653
  - ✓ यह गत वर्ष 2022-23 की तुलना से 2023-24 में 11.49 % की वृद्धि दर्शाता है।
- स्थिर (2011-12) कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय-
  - ✓ वर्ष 2023-24 - ₹90,831 (अनुमानित)
  - ✓ वर्ष 2022-23 - ₹ 84,935
  - ✓ यह गत वर्ष 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 6.94 % की वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2023-24	स्थिर मूल्यों पर	प्रचलित मूल्यों पर
राजस्थान	₹ 90831	₹ 1,67,964
भारत	₹ 1,06,744	₹ 1,84,205

सकल स्थाई पूंजी निर्माण (GFCF)

- सकल स्थाई पूंजी निर्माण को वर्ष के दौरान उत्पादनकर्ता द्वारा सृजित की गई परिसम्पत्तियों में से निस्तारित सम्पत्तियों को घटाने के बाद तथा गणना अवधि में गैर उत्पादित परिसम्पत्तियों को उत्पादन गतिविधियों में उपयोग की कीमत के आधार पर मापा जाता है।
- प्रचलित मूल्य पर GFCF (वर्ष 2022-23) - ₹ 3,99,594 करोड़ (GSDP का 29.43%)।
- वर्ष 2022-23 में GFCF में गत वर्ष 2021-22 की तुलना में 12.78 % की वृद्धि हुई।
- GFCF में योगदान
  - ✓ निजी क्षेत्र- 78.54%
  - ✓ सार्वजानिक क्षेत्र- 21.46%

नोट: गत 5 वर्षों के दौरान सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वृद्धि उतार-चढ़ाव भरी रही

GFCF में 3 सर्वाधिक योगदान देने वाले क्षेत्र

1. निर्माण
2. आवासीय भवन
3. लोक प्रशासन

मूल्य सांख्यिकी

चार्ट: थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

थोक मूल्य सूचकांक (WPI)	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)
➢ यह व्यापक रूप से मूल्यों के उतार-चढ़ाव को व्यक्त करता है और सभी प्रकार के व्यापार एवं लेन-देनों में वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन को व्यक्त करने वाला संकेतक है	➢ यह उन वस्तुओं और सेवाओं (जैसे खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि) की कीमतों में परिवर्तन की गणना करता है, जिन्हें भारतीय उपभोक्ता द्वारा उपभोग हेतु क्रय जाता हैं।
➢ विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व	➢ खाद्य पदार्थों को अधिक महत्व
➢ मासिक आधार पर जारी	➢ मासिक आधार पर जारी

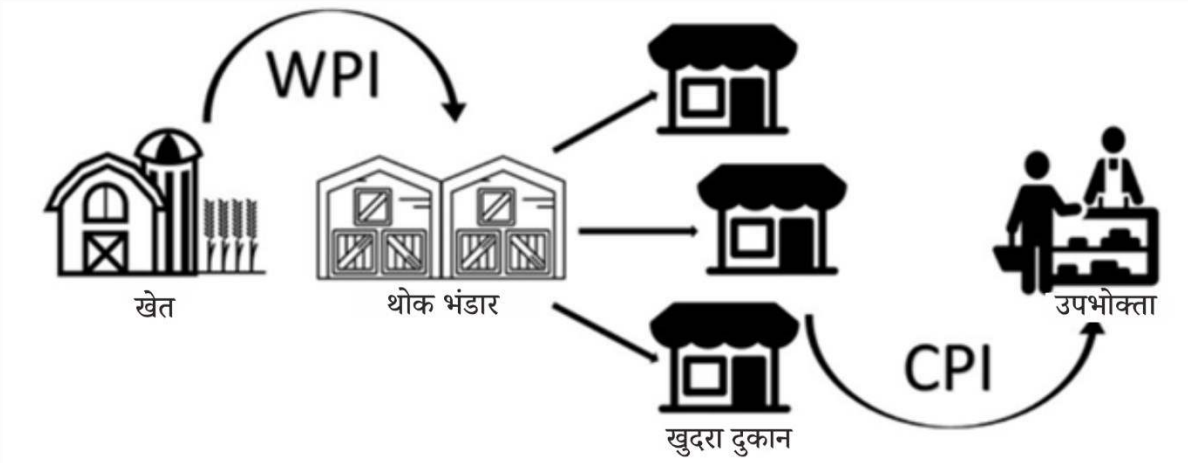

थोक मूल्य सूचकांक (W.P.I)

	आधार वर्ष	
WPI	1999-2000	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।
CPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों हेतु)	2016 (सितम्बर, 2020 से)	श्रम ब्यूरो,चंडीगढ़
CPI-AL (कृषि श्रमिकों हेतु)	1986-87	
CPI- RL (ग्रामीण श्रमिकों हेतु)		
CPI- Rural, Urban and Combined (ग्रामीण, शहरी और संयुक्त)	2012	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दिल्ली

राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक

- 154 वस्तुएं शामिल
- इसमें शामिल वस्तुओं का क्रम– प्राथमिक वस्तुएं > विनिर्मित उत्पाद > ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेहक

	संख्या	भार	वार्षिक वृद्धि
प्राथमिक वस्तुएं	75	33.894%	9.96% (Highest)
विनिर्मित उत्पाद	69	49.853%	0.23%
ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उप्स्नेहक	10	16.253%	0.39%

नोट: भारत सरकार ने WPI के लिए "वर्ष 2011-12" को आधार वर्ष माना है

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)

प्रतिमाह चार विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किये जाते है–

(अ) औद्योगिक श्रमिकों हेतु (CPI-IW)
(ब) कृषि श्रमिकों हेतु (CPI-AL)
} श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़

(स) ग्रामीण श्रमिकों हेतु (CPI-RL)

(द) ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु (CPI – R, U and C) – राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, दिल्ली

CPI-IW

- देश के 88 केंद्रों पर आधारित
- राजस्थान में 3 केंद्र:
  1. जयपुर
  2. भीलवाड़ा
  3. अलवर (अजमेर के स्थान पर)

2 CHAPTER कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

राज्य में कृषि की स्थिति-

(अ) सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA)

	स्थिर मूल्यों पर	स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर	प्रचलित मूल्यों पर	प्रचलित मूल्य पर वृद्धि दर
GSDP में कृषि का हिस्सा	26.21%	2.13%	26.72%	9.64%
संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) (वर्ष 2019 - 20 से 2023 - 24 तक)	3.86%		9.99%	

(ब) संबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रवार योगदान (प्रचलित मूल्यों पर):-

	क्षेत्र	योगदान	वृद्धि
1.	पशुधन	48.58%	5.83%
2.	फसलें	44.53%	-1.61% (कमी)
3.	वानिकी एवं लॉगिंग	6.40%	2.82%
4.	मत्स्य	0.49%	15.21%

- कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र के उप क्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2023-24 (द्वितीय अग्रिम अनुमान) में योगदान

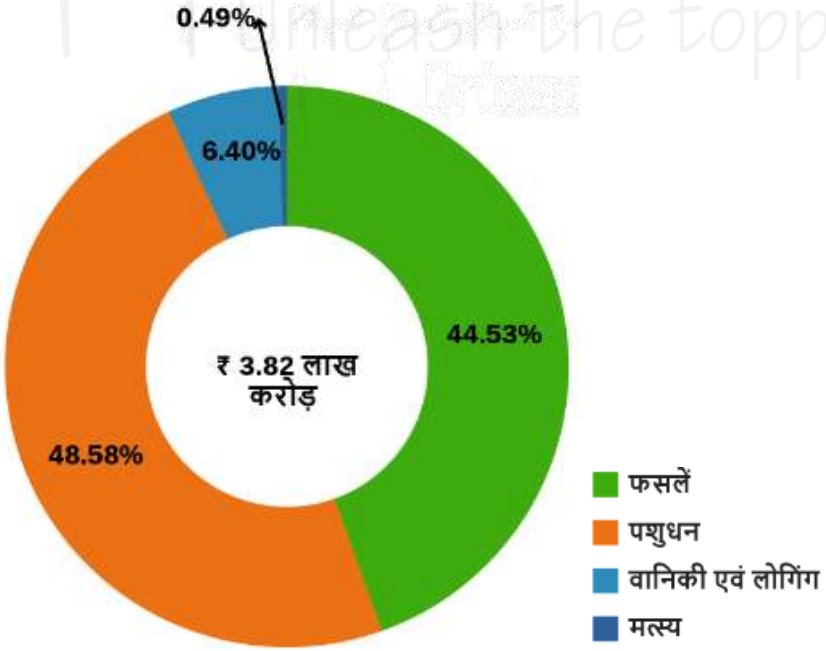

भू-उपयोग

- राजस्थान का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल - 342.81 लाख हेक्टेयर।

	भूमि के प्रकार	प्रतिशत
1.	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	53.74
2.	बंजर भूमि	10.39
3.	वानिकी	8.09
4.	ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि	6.89
5.	कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि	5.92
6.	अन्य चालू पड़त भूमि	5.68
7.	स्थायी चारागाह भूमि	4.82
8.	चालू पड़त	4.38
9.	वृक्षों के झुण्ड और बाग	0.09

भू उपयोग सांख्यिकी 2022-23

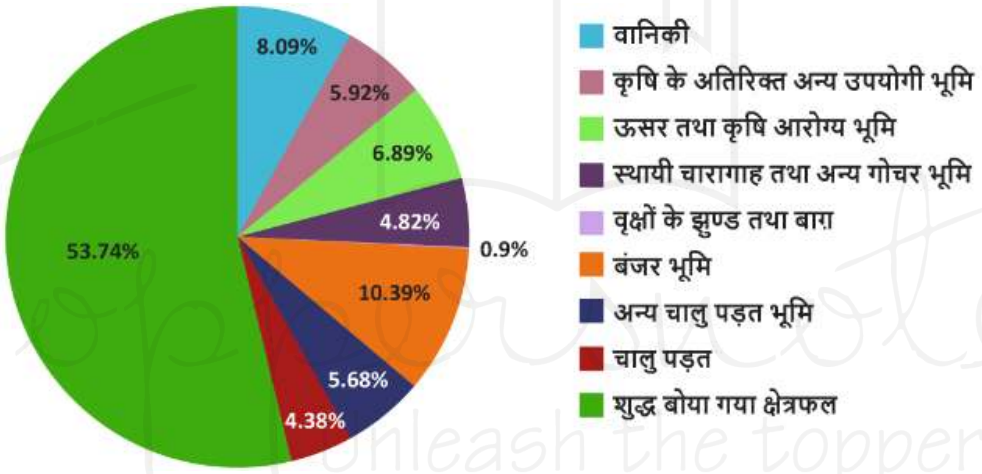

प्रचालित जोत धारक

	कृषि गणना (2015-16)	परिवर्तन (2010-11 से)
कुल प्रचालित भूमि जोतों की संख्या	76.55 लाख	11.14% (वृद्धि)
कुल जोतों का क्षेत्रफल	208.73 लाख हेक्टेयर	1.24% (कमी)
भूमि जोतों का औसत आकार	2.73 हेक्टेयर	11.07 % (कमी)

महिला प्रचालित जोत धारक

	(2015-16)	(2010-11)
संख्या	7.75 लाख	41.94 % (वृद्धि)
क्षेत्र	16.55 लाख हेक्टेयर	24.44 % (वृद्धि)

जोत धारक	आकार	परिवर्तन
सीमान्त (1.0 हैक्टेयर से कम)	40.12 %	19.79% (वृद्धि)
लघु (1.0-2.0 हैक्टेयर)	21.90 %	10.50% (वृद्धि)
अर्ध-मध्यम (2.0-4.0 हैक्टेयर)	18.50%	5.67% (वृद्धि)
मध्यम (4.0-10.0 हैक्टेयर)	14.79 %	13.20% (वृद्धि)
वृहद (10.0 हैक्टेयर एवं अधिक)	4.69%	11.14 % (कमी) कारण – जोत के आकार में कमी

कृषि उत्पादन

क्र.सं.	फसल उत्पादन	उत्पादन (लाख मीट्रिक टन में)
1.	खाद्यान्न उत्पादन	कुल 2023-24 | परिवर्तन 245.01 लाख मीट्रिक टन | 3.08 ↓ | | 2023-24 (लाख मीट्रिक टन में) | परिवर्तन | | खरीफ | 89.83 | 18.04% ↓ | | रबी | 155.18 | 8.37% ↑ | | | 2023-24 | परिवर्तन | | अनाज | 208.61 | 3.59% ↓ | | दलहन | 36.40 | 0.05% ↓ |
	तिलहन	2023-24 | परिवर्तन 101.24 | 2.10% ↓
	गन्ना	2023-24 | परिवर्तन 3.28 | 4.13% -↑
	कपास	2023-24 | परिवर्तन 26.21 | 5.58% ↓

क्र.सं.	फसल	प्रथम स्थान	द्वितीय स्थान	राजस्थान का देश के कुल उत्पादन में योगदान (प्रतिशत में)
1.	बाजरा	राजस्थान	उत्तरप्रदेश	38.98
2.	सरसों	राजस्थान	मध्यप्रदेश	46.63 (2^{nd})
3.	पोषक अनाज	कर्नाटक	राजस्थान	13.89

4.	कुल तिलहन	राजस्थान	मध्यप्रदेश	22.25
5.	कुल दलहन	मध्यप्रदेश	महाराष्ट्र	14.51
6.	मूंगफली	गुजरात	राजस्थान	16.83
7.	चना	महाराष्ट्र	मध्यप्रदेश	19.28
8.	ज्वार	महाराष्ट्र	कर्नाटक	12.67
9.	सोयाबीन	महाराष्ट्र	मध्यप्रदेश	7.12
10.	ग्वार	राजस्थान	-	87.69 (अधिकतम)

कृषि से संबंधित योजनाएं

बीज

- मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना:
  - ✓ प्रारंभ: 2017
  - ✓ प्रारंभ में 3 कृषि-जलवायुवीय खण्डों (कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर) में क्रियान्वयन ।
  - ✓ वर्ष 2018-19 से राज्य के समस्त 10 कृषि-जलवायुवीय खण्डों में क्रियान्वयन किया गया। (सम्पूर्ण राजस्थान)
  - ✓ उद्देश्य: किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
  - ✓ इस योजनान्तर्गत गेहूं, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, सरसों, मूंग, मोठ मूंगफली एवं उड़द की 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों के बीज उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सिंचाई

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2015
   - नोडल विभाग- बागवानी विभाग।
   - उद्देश्य: खेत तक पानी की पहुँच को बढ़ाना और सिंचाई सुनिश्चित करने हेतु कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना एवं खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना
   - केंद्र : राज्य = 60: 40
2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - सूक्ष्म सिंचाई (PMKSY-MI)
   - इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीकों को बढ़ावा दिया जाता है।
   - केंद्र : राज्य = 60:40
   - भारत सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान कर रही है।

उत्पादकता

1. राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन (NMAET) 2014
   - उद्देश्य:
     - ✓ कृषकों की सक्रिय भागीदारी के साथ 'रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार योजना बनाना ।
     - ✓ संसाधनों के आवंटन में ब्लॉक स्तर पर सभी हितधारकों के बीच कार्यक्रम समन्वय और एकीकरण को बढ़ाना।
     - ✓ केंद्र : राज्य = 60: 40

- इसमें 3 उप-मिशन शामिल हैं-
  - ✓ कृषि विस्तार पर उप-मिशन (SMAE)
  - ✓ बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन (SMSP)
  - ✓ कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)

2. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) 2014

- केंद्र : राज्य = 60 : 40
- NMSA के तीन उप-मिशन:-

  अ. वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD)।

  ब. मृदा स्वास्थ्य कार्ड:- प्रारंभ - 19 फरवरी, 2015 सूरतगढ़ (गंगानगर) से
  - ✓ मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस- 19 फरवरी
  - ✓ उद्देश्य:
    - मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना।
    - मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना।
    - विभिन्न फसलों के लिए विवेकपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन।
  - ✓ राज्य के सभी 352 ब्लॉकों में प्रभावी।

  स. कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF):-
  - ✓ प्रारंभ - 2017-18
  - ✓ उद्देश्य: वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना।

3. परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):

- जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग कम करते हुए कृषि उत्पादन किया जाता है।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):-

- प्रारंभ - वर्ष 2007-08
- केंद्र : राज्य = 60: 40
- उद्देश्य:
  - ✓ कृषि में निवेश को बढ़ावा देना।
  - ✓ कृषि में 4% विकास दर सुनिश्चित करना।

5. राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM):- (2005)

- राजस्थान के 24 जिलों में कार्यान्वित।
- फलों, मसालों और फूलों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन बढ़ाना।

6. सौर ऊर्जा आधारित पंप परियोजना [प्रधानमंत्री 'कुसुम' योजना घटक 'बी']

- पीएम 'कुसुम' (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान)
- प्रारंभ- फरवरी 2019 में
- मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,भारत सरकार
- योजनान्तर्गत 3 घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावॉट अतिरिक्त सौर क्षमता हासिल की जाएगी।
- पहला सौर ऊर्जा संयंत्र - भालोजी गांव (कोटपुतली)
- प्रावधान: 3 HP से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र की स्थापना।
- इस योजना के तहत –
  - ✓ कुल 60% अनुदान (केन्द्रांश – 30%, राज्यांश – 30%)
  - ✓ किसान – 30% बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है
  - ✓ 10% किसान द्वारा देय

सहयोग एवं सुरक्षा

1. तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान

- प्रारंभ- वर्ष 2017-18 में।
- नीलगाय , जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं से सुरक्षा।
- राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन में शामिल (2022-23 से दो वर्ष के लिए)।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM):-

- प्रारंभ- वर्ष 2007-08
- केंद्र: राज्य = 60:40
- वर्ष 2010-11 से राज्य के सभी जिलों को 'NFSM दलहन' में शामिल किया गया।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY):-

- प्रारंभ- 18 फरवरी, 2016
- योजना में खाद्यान्न (अनाज, बाजरा, दालें), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलें शामिल हैं।

फसल	प्रीमियम राशि
खरीफ़ →	2%
रबी →	1.5%
वाणिज्यिक/बागवानी →	5%

- सरकार द्वारा जारी संशोधित निर्देशानुसार खरीफ 2020 से असिंचित क्षेत्रों के लिये 30 प्रतिशत एवं सिंचित क्षेत्रों के लिये 25 प्रतिशत की अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

4. कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि

उच्च माध्यमिक (कृषि)	₹15000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष
स्नातक (कृषि) और स्नातकोत्तर (कृषि)	₹24000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष
पी.एच.डी	₹40000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष

कृषि विपणन

- कृषि विपणन निदेशालय - वर्ष 1974.
- कृषक कल्याण कोष/किसान कल्याण निधि
  - गठन - 16 दिसंबर 2019
- वित्त प्रावधान
  - प्रारंभिक प्रावधान - 1,000 करोड़ रुपये
  - जिसमें वृद्धि करके 7,500 करोड़ रुपये किया गया
- कृषि विपणन नीति:
  - राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 (12 दिसंबर, 2019).(आर्थिक समीक्षा- 2022-23 के अनुसार)

कृषि विपणन की अन्य योजनाएँ

1. मुख्यमंत्री/राजीव गांधी कृषक साथी योजना:-
   - प्रारंभ - 2009
   - कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर 2 लाख की सहायता
   - लाभार्थी- : किसान, कृषि मजदूर, हम्माल (कुली)
2. महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना - (2015)
   - विशेषताएं

     अ. गर्भावस्था सहायता - 45 दिनों की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि ।

     ब. विवाह सहायता: -
     - महिला श्रमिक को स्वयं की शादी के लिए-50,000 रुपये
     - पुत्री विवाह(अधिकतम -2) के लिए- 50,000 रुपये

     स. छात्रवृत्ति: - लाइसेंस प्राप्त मजदूर के बेटे/बेटी को 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।

     द. चिकित्सा सहायता - गंभीर बीमारी पर अधिकतम 20,000 रुपये

     इ. पैतृक अवकाश - 15 दिनों की मजदूरी के समतुल्य राशि का पैतृक अवकाश।
3. कृषक उपहार योजना
   - ई-नाम पोर्टल - जनवरी 2022
   - प्रत्येक 10 हजार (या इसके गुणक) की बिक्री पर डिजिटल कूपन जारी किया जाएगा।
4. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (PM-FME):-
   - देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को उन्नत करना।
   - राज्य में नोडल एजेंसी - राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   - केंद्र : राज्य = 60: 40
   - कार्यावधि- 5 वर्ष (2021 से 2024-25 तक)

Toppersnotes
Unleash the topper in you

5. सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना:

- कृषि उपज की बिक्री पर ई-भुगतान को बढ़ावा देना।
- 50,000 से अधिक के ई-भुगतान पर, महिला किसान के बैंक खाते में 1000 की वित्तीय सहायता।

आधारभूत संरचना विकास हेतु:-

1. प्रत्येक जिले में मिनी फूड पार्क की स्थापना (बजट 2021-22)
2. रीको (RIICO) द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना [बोरानाडा (जोधपुर), रनपुर (कोटा), अलवर, श्री गंगानगर]
3. भारत सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना [रूपनगढ़ (अजमेर), मथानिया (जोधपुर), पलाना (बीकानेर)]

जल संसाधन

- राज्य में कुल 39.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।
- वर्ष 2022-23 के दौरान 8 वृहद परियोजनाएं, 5 मध्यम परियोजनाएं (गरदरा, टाकली, गागरिन, ल्हासी एवं हथियादेह तथा 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं।

महत्वपूर्ण वृहद सिंचाई परियोजनाएं:

परवन वृहद् परियोजना	➢ निर्माण- 'परवन' नदी (झालावाड़) ➢ लाभान्वित क्षेत्र- झालावाड़, बारां, कोटा
धौलपुर लिफ्ट	➢ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई और पेयजल परियोजना।
नर्मदा नहर परियोजना	➢ भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ। ➢ जालौर और बाड़मेर जिलों का कमांड क्षेत्र।
नवनेरा बैराज	➢ पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का अभिन्न हिस्सा ।
कालीतीर लिफ्ट	➢ पार्वती और रामसागर बांध से धौलपुर जिले (483 गावों, 3 बस्तियों) की पेयजल मांग की आपूर्ति के लिए ।
अपर हाई लेवल नहर परियोजना (माही)	➢ माही परियोजना का "सैडल" बांध।
पीपलखूंट हाई लेवल नहर परियोजना	➢ माही बांध से जाखम बांध तक।
राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (RWSLIP)	➢ जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जायका) द्वारा वित्तपोषित। ➢ उद्देश्य: मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि सहायता सेवाओं में सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता और कृषि उत्पादकता में सुधार करके किसानों की आजीविका में सुधार करना।
राजस्थान मरू क्षेत्र हेतु जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (RWSRPD)	➢ न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित। (70% तक) ➢ लाभान्वित क्षेत्र-श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर और बाड़मेर जिले।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना:-

- वित्त पोषण- जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार + विश्व बैंक द्वारा
- लागत- 134 करोड़ (भारत सरकार से 100% अनुदान)
- परियोजना अवधि- 8 वर्ष (2016 से सितंबर 2025)
- नोडल विभाग - जल संसाधन विभाग, राजस्थान
- कार्यवाही- पारदर्शी जल प्रबंधन के लिए, सबसे पहले बीसलपुर बांध और जवाई बांध के साथ-साथ 7 बांधों और 2 नहरों (गंग-भाखड़ा नहर प्रणाली और नर्मदा नहर प्रणाली) पर SCADA (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) प्रणाली स्थापित की गई है।

इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की री-लाइनिंग:-

- भारत सरकार और पंजाब सरकार के बीच समझौता ज्ञापन
- केंद्र-60%, राज्य-40%.
- सरहिंद फीडर
  - पंजाब (54.15%)
  - राजस्थान (45.85%)
- राजस्थान को केंद्र सरकार से 60% हिस्सा राशि प्राप्त होगी।

रिपेयर-रिनोवेशन -रिस्टोरेशन परियोजना (RRR Project) -

- प्रारंभ - जनवरी, 2005
- वर्ष 2017-18 में इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' में शामिल किया गया।
- केंद्र: राज्य = 60: 40
- वर्तमान में राज्य की 37 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया है।

भू-जल संसाधन

- भू-जल संसाधनों का आंकलन प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में किया जाता है।
- भू-जल, उपलब्धता के आधार पर- 302 ब्लॉक में से
  - सुरक्षित: 38
  - विषम : 23
  - अति दोहित: 216
- राज्य में भू-जल दोहन की दर 150% है।

अटल भूजल योजना

- भारत सरकार और विश्व बैंक (50:50) के सहयोग से शुरुआत
- प्रारंभ- 1 अप्रैल, 2020
- अवधि:- 2020-21 से 2024-25 तक (5 वर्ष)
- योजना में शामिल 7 राज्य - हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
- उद्देश्य: सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल स्तर और प्रबंधन में सुधार करना।
- नोडल विभाग - भूजल विभाग।

Toppersnotes Unleash the topper in you

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0

- राज्य की 349 पंचायत समितियों में चरणवार तरीके से 5000 से 8000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन कर जल संग्रहण और संरक्षण कार्य करवाए जायेंगे ।

वाटरशेड विकास

- राज्य में उपलब्ध कुल जल संसाधनों का 1.16%।

पशुपालन

- देश के कुल पशुधन का 10.60% पशुधन राजस्थान में है।

पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान उठाये गये प्रमुख कदम

1. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM):-
   - ✓ इसके अंतर्गत भेड़ और बकरी के आनुवांशिक सुधार (GIGS) योजना की शुरुआत की गई है।
     - प्रदर्शनी और प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
     - केंद्र: राज्य = 60: 40
     - 9 जिलों में योजना का प्रसार
   - पशुपालकों को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण व्यवस्था।
2. पशुमित्र योजना
   - ✓ पशुपालकों को डोर स्टेप सुविधाओं हेतु जैसे-टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, पशु नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण आदि
3. कामधेनू बीमा योजना
   - ✓ दुधारू गौ/भैंस वंश पशुओं के लिए।
   - ✓ निःशुल्क बीमा 40,000 रुपये तक प्रति पशु (प्रत्येक परिवार के लिए दो पशु

राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालन से संबंधित योजनाएं:

1. मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना:
   - ✓ प्रारंभ- 15 अगस्त, 2012
   - ✓ पशु रोगों की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला पशु चिकित्सा केंद्र की स्थापना।
2. खुरपका-मुंहपका रोग:-
   - ✓ भारत सरकार की योजना
   - ✓ प्रारंभ- वर्ष 2010 में
   - ✓ केंद्र: राज्य = 60: 40

गोपालन विभाग

- स्थापना- 13 मार्च, 2014
- उद्देश्य: राज्य में देशी नस्ल के पशुओं के संवर्धन, संरक्षण और विकास के लिए कार्यक्रम।

1. राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना:-
   - ✓ प्रारंभ- 1 जनवरी, 2022
   - ✓ डेयरी उत्पादकों की आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5.00 लाख रुपये तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपये की बीमा राशि देय।
   - ✓ 8वां चरण प्रारंभ- 1 फरवरी, 2024 से।
2. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना:-
   - ✓ प्रारंभ- 1 फरवरी, 2019
   - ✓ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में दुग्ध उत्पादकों के लिए सहायता अनुदान राशि 2 प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 प्रति लीटर किया गया।
3. नंदी गोशाला जन सहभागिता योजना
   - ✓ उद्देश्य- घुमंतू और आवारा नर गौ वंश की समस्याओं से निपटना है।
4. गौशाला/पशुआश्रय स्थल योजना
   - ✓ आवारा मवेशियों की समस्या को दूर करने के लिए जन सहभागिता शुरू की गई है।
5. वध से बचाए गोवंश योजना
   - ✓ बड़े मवेशियों के लिए 40 रुपए प्रतिदिन तथा छोटे मवेशियों के लिए 20 रुपए प्रतिदिन की दर से गौशाला में मवेशियों को रखने की अवधि या एक वर्ष, जो भी कम हो, के लिए सहायता प्रदान करना।

मत्स्य पालन

- ➢ उद्देश्य:
  - ✓ प्रोटीन युक्त सस्ता भोजन
  - ✓ ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों को रोजगार
- ➢ जल संसाधनों के आधार पर राजस्थान देश में 10वें स्थान पर है।
- ➢ राजस्थान की मत्स्य उत्पादन क्षमता- प्रतिवर्ष 80,000 मीट्रिक टन से अधिक है।
- ➢ वर्ष 2023-24 में मत्स्य उत्पादन - 91,349.43 मीट्रिक टन ।
- ➢ मत्स्य विभाग द्वारा आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु महत्वाकांक्षी योजना 'आजीविका मॉडल', जो शून्य राजस्व मॉडल है, राज्य के तीन जलाशयों जयसमन्द (सलूम्बर), माही बजाज सागर (बांसवाड़ा) एवं कडाना बैक वाटर (डूंगरपुर) में प्रारम्भ की गई है।
- ➢ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर. के. वी. वाई.) के अन्तर्गत मत्स्य प्रसंस्करण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिये रामसागर (धौलपुर), बीसलपुर (टोंक) एवं राणा प्रताप सागर (रावतभाटा), जवाई बांध (पाली) एवं जयसमन्द (सलूम्बर) बांधों से मत्स्य लेण्डिंग केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- ➢ भारत सरकार द्वारा पिछली नीली क्रांति योजना के सभी घटकों को मिलाकर वर्ष 2020-21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है।

नोट: 2 मत्स्य फ़ीड मील, मछली पालन पोंड निर्माण और केज कल्चर यूनिट (झालावाड़ जिले में 3) प्रस्तावित।